ऋण लेकर प्रभावितों को राहत देने के प्रयास: गहलोत

नगर प्रतिनिधि
जयपुर, 30 मई।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में अकाल की विभीषिका से निपटने के लिए धन की कमी होने के बावजूद हम ऋण लेकर प्रभावितों को राहत पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने केन्द्र सरकार से राजस्थान को विशेष रूप से राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से मदद करने का अनुरोध किन्तु केन्द्र ने पर्याप्त राशि आवंटित नहीं की।

गहलोत मंगलवार को यहां शासन सचिवालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मसूरी में बैठे अखिल भारतीय सेवा के प्रशिक्षुओं तथा जैसलमेर से 70 किलोमीटर दूर फतेहगढ़ ग्राम पंचायत की ग्रामसभा में बैठे जिला कलेक्टर, पंच, सरपंच तथा ग्रामीणों से रूबरू होकर उनके सीधे संवादों का जवाब दे रहे थे।

इस तकनीक के अंतर्गत जयपुर मसूरी एवं जैसलमेर में एस.सी.पी. सी.वी.सेट (वेरी स्माल एपरचर टर्मिनल) स्थापित किए जाकर उपग्रह के माध्यम से जोड़े गए थे। इसका स्विचिंग दिल्ली स्थित केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष द्वारा किया जा रहा था जिसके माध्यम से वीडियो एवं श्रव्य सिगनल्स से आदान प्रदान सम्पादित किया गया। प्रशिक्षुओं में मुख्यमंत्री तथा जिला कलेक्टर सरपंच व ग्रामीणों से राज्य में अकाल की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों तथा अकाल प्रभावित लोगों व पशुओं को पहुंचाई जा रही राहत के बारे में सवाल किए। यह वीडियो कांफ्रेंसिंग राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय के सहयोग से लाल बहादुर शास्त्री

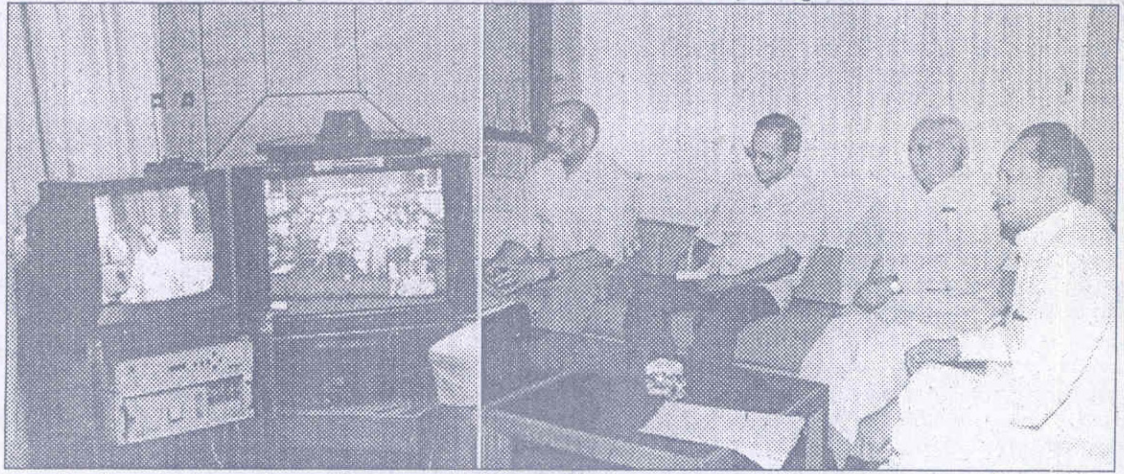

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को शासन सचिवालय जयपुर में वीडियो कान्फ्रेंसिंग से मसूरी (उत्तर प्रदेश) में बैठे अखिल भारतीय प्रशिक्षकों से संवाद करते हुए।

राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी एवं राष्ट्रीय केन्द्र भारत सरकार द्वारा आयोजित की गई थी।

मसूरी से अकादमी के निदेशक वी.एस. बासवान एवं पाठ्यक्रम समन्वयक यदुवेन्द्र माथुर तथा 1999 बेच के 53 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया।

अकादमी के एक प्रशिक्षु के राहत कार्यों के लिए धन की आवश्यकता के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि अकाल से निपटने के लिए केन्द्र सरकार को 1145 करोड़ रुपए की मदद देने का ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसकी एवज में राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 103 करोड़ रुपए की सहायता दी गई तथा प्रधानमंत्री सहायता कोष से 20 करोड़ रुपए की मदद दी गई। उन्होंने कहा कि हम इस राशि को पूल करके प्रभावितों को राहत पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम नाबार्ड से 144 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त कर प्रभावितों को राहत पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारे की कमी वाले जिलों में पशु शिविर संचालित किए जा रहे हैं। बड़े पशु के लिए 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक जून से अकाल राहत कार्यों पर 17 लाख 50 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

टास्क फोर्स के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में गहलोत ने कहा कि अकाल राहत कार्यों की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री अकाल राहत मंत्री एवं मुख्य सचिव के स्तर पर एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। हम सर्व समन्वय की भावना से संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं ताकि जनता को इस कठिन परिस्थिति में राहत मिल सके। परम्परागत जल स्रोतों के बारे में जानकारी चाहने पर मुख्यमंत्री ने परंपरागत जल स्रोत की आवश्यकता को समय की मांग बताते हुए कहा कि राज्य सरकार ने परंपरागत कुओं, बावड़ियों, नाड़ियों तथा खडीनों इत्यादि का जीर्णोद्धार एवं संरक्षण पंचायतों के माध्यम से कराने का निश्चय किया है। उन्होंने कहा कि हम नवनिर्मित मकानों में वर्षा के जल संग्रहण के लिए टांकों का प्रावधान रखने को अनिवार्य करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पुन: पत्र लिखकर 700 करोड़ रुपए की मांग की है तथा श्रमिकों को काम के बदले अनाज योजना के तहत दिए जाने वाले गेहूं को अनुदान के रूप में देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात को आवंटित गेहूं की ग्रांट के रूप में स्वीकृति नहीं देने पर राजस्थान को केन्द्र से मिलने वाले गेहूं के बदले राज्य सरकार को 80 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा।